भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 335
उत्तर देने की तारीख 06 फरवरी, 2025

भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन

335. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतनेट परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने गांवों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है;

(ख) भारतनेट परियोजना के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और विगत पांच वर्षों के दौरान इस निधि के उपयोग की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है, यदि हां, तो सरकार द्वारा परियोजना के सफल और समय पर कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदत्त ग्राम पंचायतों (जीपी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची और संवितरित/उपयोग की गई धनराशि का विवरण डिजिटल भारत निधि की वेबसाइट (https://usof.gov.in/en/home) पर उपलब्ध है।

(ग) भारतनेट देश के सुदूर क्षेत्रों तक फैली हुई एक मेगा परियोजना है जो दुर्गम इलाकों (पहाड़ी/पथरीले) के साथ-साथ वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों को कवर करती है। राज्य एजेंसियों से, विशेष रूप से, वन क्षेत्रों में मार्गाधिकार की अनुमति प्राप्त होने में देरी, कोविड वैश्विक महामारी के कारण आवाजाही पर प्रतिबंध, पानी की पाइप लाइन बिछाने,

सड़क चौड़ीकरण और अन्य निर्माण गतिविधियों जैसे विकास कार्यों के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) को नुकसान जैसे विभिन्न कारणों से परियोजना कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

इस परियोजना के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड (बीबीएनएल/बीएसएनएल) द्वारा गहन निगरानी की जा रही है और संबंधित राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा राज्य-नेतृत्व वाले मॉडल के तहत, इस परियोजना की प्रगति की निगरानी करने और मुद्दों के समयबद्ध तरीके से समाधान हेतु संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समितियाँ भी गठित की गई हैं।

*****